(घ) क्या यह भी सच है कि इनमें से कुछ तेल शोधक कारखानों की स्थापना का कार्य पहले से ही चल रहा है; और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा इनके कार्य के पूरा होने की निर्धारित तिथियां क्या-क्या हैं ; और

(ङ) देश में 670 लाख टन की शोधन क्षमता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ङ) फिलहाल देश में कुल शोधन क्षमता 51.85 मि. टन प्रतिवर्ष है । मांग में भविष्य में होने वाली वृद्धि को पूरा करने के लिए वर्तमान रिफाइनरियो का विस्तारण करके गत्यवरोध को दूर करके अतिरिक्त शोधन क्षमता का सृजन किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप शोधन क्षमता में 8.65 मि० टन प्रतिवर्ष तक वृद्धि होगी। करनाल मंगलोर,नुमालीगढ़ तथा नारीमनम में नई रिफाइनरियों के परिणामस्वरूप 12.5 मि. टन प्रतिवर्ष की अतिरिक्त क्षमता का सृजन होगा । ये परियोजनाएं अनुमोदन/कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं ।

तेल की खोज

1078. **श्रीमती सत्या बहिन :**
डा. अबरार अहमद :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री 15 जुलाई, 1991 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 89 को दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल की खोज के लिए किस अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है ; ताकि भूमिगत स्रोतो से अधिकतम तेल निकाला जा सके ;

(ख) क्या इस संबंध म किसी अन्य देश से सहायता प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है ; यदि हां, तो यह सहायता किस प्रकार की होगी तथा किन-किन देशों से प्राप्त की जायेगी ; और

(ग) क्या इसके लिए कोई शर्तें हैं, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) भूकम्प और तेल और गैस के संभावित स्थानों का पता लगाने के लिए अन्य प्रकार के सर्वेक्षणों के साथ-साथ हाइड्रोकार्बन निकालने के लिए प्रौद्योगिकियों अर्थात् खुदाई, भंडारण उत्प्रेरक और तेल प्रति प्राप्ति तकनीकियों इत्यादि के लिए विभिन्न परिष्कृत प्रौद्योगिकियो का प्रयोग किया जा रहा है ।

(ख) ऐसी प्रौद्योगिकियां बहुराष्ट्रीय कंपनियो और यू.के० तथा सोवियत यूनियन जैसे देशो के साथ हुए सर्विस ठेको और द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रमों की तहत प्राप्त की जाती है ।

(ग) ये प्रबन्धक केवल सामान्य संविदात्मक दायित्वों के तहत होती है ।

विमान सेवाओं का निजीकरण

1079. **श्री राधाकिशन मालवीय** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विमान सेवाओं के क्रमबद्ध तरीके से निजीकरण करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अभी तक क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों के पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्रों को ऐसे निजीकरण से कोई लाभ पहुचेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) (क) और (ख) सरकार ने निम्नी पार्टियों द्वारा अन्तर्देशीय

विमान सेवाओं के प्रचालन के ढांचे को उदार बनाया है । अब देश में निजी पार्टियों द्वारा प्रचालित सेवाओं के संबंध में विमान के आकार, मार्गों, अनुसूचियों, किरायों और प्रचालन के लिए हवाई अड्डों के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

(ग) निजी हवाई टैक्सी प्रचालकों को देश भर में और अधिक स्थानों को विमान सेवाओं से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ।

भारत में विमान किराये

1080. **श्री राधाकिशन मालवीय :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विमान सेवाओं के वर्तमान किराये केलकर समिति की सिफारिशों के अनुरूप हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का केलकर समिति की सिफारिशों के प्रति क्या दृष्टिकोण है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं

(ख) यह निर्णय किया गया है कि भविष्य में अंतर्देशीय विमान किराए में परिवर्तन करते समय केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा ।

राष्ट्रीय ताप विद्युत पारेषण निगम का कार्यकरण

1081. **श्री रणजीत सिंह :** क्या **विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत पारेषण निगम की स्थापना देश में उत्पादित विद्युत का प्रभावी रूप से पारेषण करने की व्यवस्था करने के ध्येय से की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त निगम की स्थापना कब की गई थी ;

(ग) क्या यह निगम अपने कर्तव्यों का उचित रूप से निर्वाह कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम 23 अक्तूबर, 1989 में निगमित किया गया था ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत यूटिलिटियों के सहायक उपस्कर एवं सम्बद्ध सुविधाओं सहित सभी पारेषण लाइनें एवं उपकेन्द्र राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम लि० (एन०टी०टी०सी०) द्वारा चरणबद्ध ढंग से अपने आधिपत्य में ले लिए जायेंगे ।

Development of Tourism in Rajasthan

1082. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether Government are aware that during the year 1990 Rajasthan State received about 40 per cent of the total inflow of international tourists in the country besides a large number of domestic tourists;

(b) whether Government of India propose to clear all the pending proposals submitted by the State Government of Rajasthan pertaining to development of tourism in that State; and

(c) if so, what are the details thereof indicating the total central assistance given so far or likely to be given?